

सम्पादकीय

मानसून का वापसी

दरा के उत्तर-पश्चिम से नानूरू का पापसा का विद्युतीय बन रहा है और इसी के साथ चार माह के बरसात का मौसम अपने अंत की ओर अग्रसर है। देश की आधी से अधिक खेती शिंचाई के लिए मॉनसून पर निर्भर करती है, जो अमूमन जून में केरल से शुरू होता है तथा इसका अंतिम चरण सितंबर के मध्य में राजस्थान से प्रारंभ होता है। पूर्वोन्मानों में बताया गया था कि इस वर्ष मॉनसून सामान्य रहेगा, लेकिन जून से सितंबर के बीच देश के अनेक हेस्सों में कम बारिश हुई, जबकि दक्षिणी-पश्चिमी मॉनसून के समाप्त होने वें देरी से कई जगहों पर अधिक बरसात हुई। रिपोर्टों की मानें, तो आठ राज्यों में पानी कम बरसा है। इस कारण धान की उपज को लेकर चिंताएं बढ़ता हो गयी हैं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के पहले तीन महीनों में तापमान अधिक होने से गहूं की फसल पर असर पड़ा था।

लगा है, तो दूसरी तरफ बाजार में अनाज महंगा बिक रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा बुलेटिन में छपे एक लेख में भी रेखांकित किया गया है कि मॉनसून की वापसी में देरी से खाद्यान्न कीमतों पर फिर से दबाव बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। सितंबर की अनियमित बरसात ने गर्मी से कुछ राहत तो दी है, परंतु इस वजह से कुछ मुख्य सज्जियाँ के भाव बढ़ गये हैं। मॉनसून की अनियमितता के दो मुख्य हिस्से हैं— एक, लंबे समय तक बारिश का नहीं होना तथा दूसरा, थोड़े ही अंतराल में बहुत अधिक बरसात होना। बादल फूटने की घटनाएँ, सूखे जैसी स्थितियाँ, औचक बाढ़ आदि आम होते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता बढ़ने तथा लगातार कमज़ोर व अनियमित मॉनसून के पीछे प्रधान कारक जलवायु परिवर्तन है। इसी के कारण तापमान भी बढ़ता जा रहा है तथा जाड़े का मौसम छोटा होने लगा है।

इससे प्रभावित हैं, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह स्थिति कर्हीं अधिक चिंताजनक है। बहुत बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पर्यावरण को बेहतर बनाना तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना जैसे कार्य दिन-ब-दिन चुनौतीपूर्ण होते जायेंगे। पानी का संकट, मेहमानी का क्षरण, वनों का लोप, नदियों में गाद भरना, पारिस्थितिक असंतुलन, जल, वायु व मिट्टी का प्रदूषण समुद्री जल स्तर बढ़ने से तीव्र इलाकों से प्रलयन जैसी समस्याएं मुँह बाये खड़ी हैं। जलवायु संकट से निपटने के उपायों को गंभीरता से अपनाने की आवश्यकता है।



जस-जस राहुल गांधी का पद यात्रा आगे बढ़ रही है, वह अनेकानेक तरह की आशाओं और आशंकाओं को अपने में समाहित कर रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो के नाम से हो रही यह पैंया-पैंया वाली यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंचते हुए देश, लोकतंत्र और भारत के राजनैतिक विमर्श को क्या-क्या प्रदान करेगी, यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। फिर भी इतना जरूर है कि सफलता या असफलता दोनों परिस्थितियों में इसका उल्लेख हमेशा होगा। अगर यह कामयाब हुई तो एक विकल्प के रूप में देश को फिर से मजबूत कांग्रेस मिलेगी और असफल हुई तो भी सत्ता से लड़ने का भूला-बिसरा तरीका पुनः देशवासियों के हाथ में लग जायेगा। जनता का वह आंदोलनकारी रूप एक बार फिर से उठ खड़ा होगा जो सत्ता के कान उमेठने और उसे सही राह पर चलते रहने की चेतावनी देगा। पहली व सबसे बड़ी आशा तो यही है कि इससे सड़कों पर विरोध एवं प्रदर्शनों का महत्व फिर से स्थापित होगा। पिछले 8-9 वर्षों से जहाँ एक ओर नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने खिलाफ उठने वाली सभी आवाजों को कुचला है और संवाद के तमाम लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्मों को विचार-विमर्श के लिये बन्द कर दिया है, वहीं उनकी भारतीय जनता पार्टी एवं सम्बन्धित संगठनों ने लोगों के मन में यह बात बैठा दी है कि मोदी सरकार के खिलाफ कुछ कहना मानों देश के विरोध में होना है। एक सुनियोजित एवं संगठित तरीके

उत्तरांत्रिका का जन्म हा इसा वात्रांजि से था है, तो गवलत न होगा। 1906 में गांधी जी के रहते दक्षिण अफ्रीका में सवाल में रंग भेद पर आधारित एक नून लाया गया था। भारतीय गरिकों के लिये यह पंजीकरण का अधिनियम भेदभाव एवं अन्याय पर आधारित था। इसके खिलाफ गांधी ने अभग 2200 लोगों की पद यात्रा न्यू इंसल से ट्रांसवाल तक निकाली थी। वे द ग्रेट मार्च के नाम से जाना जाता है। इस विरोध के कारण अंततः पनियेशिक सरकार को वह काला नून वापस लेना पड़ा था और उसने भारतीय राहत अधिनियम लागू किया। हनदास करमचंद गांधी से भाई, फिर पूर्ण और अंततः महात्मा बनने की क्रेयो में इस मार्च का प्रमुख हाथ यह ऐसी शुरुआत थी जिसकी शिरेण्टि 15 अगस्त, 1947 को स्वाधीन भारत के रूप में हुई थी। गांधी ने भरत में भी अपनी यात्राओं को जारी बना था। उनकी यात्राओं में कभी रोध, कभी अधिकार की मांगें तो भी संवेदना के तत्व होते थे। द ग्रेट मार्च भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ तो वहीं दाढ़ी यात्रा अधिकार को कर थीय और आजादी के समय एवं में भड़के दंगों के बीच नोआखली यात्रा का सम्बन्ध मानवीय संवेदना और करुणा से था। अनायास ही सही, तीनों तत्वों का सम्मिश्रण राहुल यात्रा में देखने को मिल रहा है। उनकी पद यात्रा में निरंकुश शासन विरोध है तो भूख, गरीबी, बेरोजगारी और दूर करने की मांग भी। लोगों का उत्तरांत्रिका, उत्तर, उत्तर, उत्तर लिपटना, उन्हें छोटी-छोटी वस्तुएं प्रदान करना।।। सारा कुछ भारत के नेहरू परिवार के साथ भावनात्मक लगाव व अपनत्व का परिचायक है—ये तीनों ही बातें (निरंकुशता का विरोध), मूलभूत सुविधाओं की मांग और भावनात्मक एका) देश को जोड़ती हैं। श्वारत जोड़े यात्रा अपने नाम के अनुरूप चरितार्थ हो रही है। 3570 किलोमीटर चलने के लिये निर्धारित यह यात्रा अपने प्रारम्भिक चरणों में तो सफल होती दिख रही है। विरोधी अर्थात् भाजपा, उसके समर्थक, उसका आईटी सेल एवं विरोधी तत्व राहुल गांधी की टी शर्ट, कथित लग्जरी कंटेनरों आदि के मामलों में नाकाम होने बाद पस्त हैं। अब वे ही कट्टर समर्थक राहुल की यात्रा को बुरा—भला कह रहे हैं जो भाजपा या सम्बन्धित संगठनों के सदस्य हैं। जातिवादी, साम्राज्यिक, खाये—पीये अद्याये वर्ग

जा इस सामाजिक प्रयोगके बराबरी से लाभान्वित हुए हैं, केवल वे ही इस यात्रा का अब भी विरोध कर रहे हैं यह अन्यथा इस यात्रा को लोकतंत्र के समर्थन में खड़ा हर व्यक्ति समर्थन दे रहा है। यहां तक कि जो सिविल सोसायटियां कभी कांग्रेस के खिलाफ थीं, वे भी आज उनके साथ इस यात्रा में शामिल हैं। इस यात्रा से उत्साहित होकर ही कांग्रेस इसी वर्ष असम में 300 किलोमीटर की यात्रा निकाल रही है जो 1 नवम्बर से प्रारम्भ होगी। ऐसे ही, पार्टी दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि पर यानी 31 अक्टूबर को ओडिशा में लम्बी पद यात्रा आयोजित कर रही है। अगले साल गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक (पश्चिम से पूर्व तक) की भी पद यात्रा होगी। इस तरह देखें तो पद यात्रा के महत्व का एक बार फिर से प्रतिपादन हो रहा है जो भारतीय लोकतंत्र के लिये शुभ संकेत है। —डॉ। दीपक चाचपोर

संबंधित आपूर्ति शृंखला
एकर्षित करने का मौका
कुर्स दिया है। जितेशक
सदस्य इनमें से किसी आधार
हो सकता है। यहां भी भारत



समझौता नहीं था, बल्कि इसका एक उद्देश्य एशिया में भविष्य के व्यापार नियमों को प्रभावित करना तथा चीन के बढ़ते वर्चस्व का प्रतिकार करना भी था। इसीलिए इसमें निवेश नियमों, श्रम एवं पर्यावरण मानकों, मूल्य शंखला का अंतरसंबंध व्यापक करना जैसे अनेक प्रावधान भी हैं। ट्रांस पैसिफिक भागीदारी महत्वाकांक्षी है और अब यह इतना आकर्षक हो गया है कि चीन भी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन भी सदस्यता के इच्छुक हैं। ध्यान रहे, 2018 से ही जापान का मुक्त व्यापार एक पैर इसमें है। इस समझौते (और चीन के नेतृत्व वाले भागीदारी समझौते से भी) से अलग रहने का खामियाजा अमेरिका भुगत रहा है। उसके व्यापार अवसर छूट रहे हैं और उसका भू-राजनीतिक प्रभाव सिमट रहा है। यही कारण है कि इंडो-पैसिफिक फ्रेमवर्क की स्थापना के लिए उसने अतिसक्रियता दिखायी है। इस समूह में 14 देश हैं और वैश्विक जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी 28 फीसदी है। इसके चार आधार हैं— व्यापार, आपूर्ति शृंखला, कराधान और भ्रष्टाचार विरोध तथा स्वच्छ ऊर्जा। फ्रेमवर्क का कोई भी

र से अलग रखा है। भारत के मंत्री ने कहा कि चूंकि श्रम एवं रण मानकों, डिजिटल व्यापार और निक खरीद जैसे मुद्दे शामिल हैं इन पर सदस्यों में आम सहमति है, इसीलिए भारत ने अपने को रखा है। उन्होंने यह भी संकेत कि अमेरिका और जापान जैसे द्वारा थोपे गये उच्च श्रम मानक जैसे विकासशील देश के लिए हो सकते हैं। इसका स्पष्ट बह है कि भारत निम्न श्रम सुरक्षा को अनुपालन करता रहेगा या पर्यावरण के लिए खतरनाक को कमज़ोर कानूनों के जरिये देता रहेगा, ताकि वैश्विक व्यापार की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हो, वे दिन अब अतीत हो चुके हैं। ने पश्चिम के ढर्ड पर श्रम एवं रण मानकों को अपनाने का वादा है, क्योंकि वह यूरोपीय संघ से यापार समझौते के लिए प्रयासरत से मैं व्यापार से अलग रहने का चुकूक है? असल में, क्षेत्रीय आर्थिक दारी से अलग होने के तुरंत बाद भरत सक्रियता के साथ ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार तों के लिए कोशिश करता रहा केर इंडो-प्रशांत भागीदारी जैसे योगी समझौतों में शामिल होने में क्यों है? भारत का विकास मुख्य

अंत के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। अपरे शुल्क उदार होने चाहिए तथा अपनी धरेलू उद्योग को वैशिक प्रतिस्पृष्ठ से बचाने के लिए लगातार संरक्षण की तरफ आये के उपायों से भी परहेज करना चाहिए। वैशिक भागीदारी से मूल्य संवर्द्ध के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 'चाइना प्लस वन' से पैदा हुए कंपनियों के हमेशा नहीं होंगे। यह हमारे अपक हित में है कि हम हर क्षेत्र में कंपनियों का या लगभग मुक्त व्यापार को बनायें। वैशिक अर्थव्यवस्था मंदी के बावजूद सुस्त होती जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर हमारी व्यापारिक संस्कृति अपनी में तीन-चार फीसदी की बढ़ोतरी होती है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत नसाहजनक होगा। और, यह तभी भव होगा, जब हम खुले और मुक्त व्यापार को लेकर कम आशंकित होंगे।

अजीत रानाडे

भावपूर्ण शृद्धां को वो

दिसम्बर सन् 1963
कानपुर की धरती पर
खोलने वाले
मेडी की दुनिया के

The image is a collage of three distinct photographs. On the left, a close-up shot shows the lower half of a woman's face, focusing on her wide, joyful smile. In the center, a product box for 'Nature's Friend Apple' detergent is displayed, featuring a green and white design with an apple illustration. On the right, a portrait of a man with dark hair, a prominent mustache, and a small red mark on his forehead (likely a tilak) is shown from the chest up, wearing a black shirt.

है संघर्ष के दौरान 21 सितम्बर को जब उनके निधन की सूचना मिली तो उनका हंसता मुख्युराता चेहरा नाचने लगा। लोग यकीन नहीं कर पाए रहे थे तो कलाकार अब चिरनिद्रा में लीन हो गया है। राजू श्रीवास्तव का इस तरह को अन्दर तक हिला गया। बोझिल मन लिए लोग दिन भर उनकी यादों में खराब थीं, समूचा देश उनके ठीक होने की प्रतीक्षा में था। दिल्ली के एस्स दिन पहले उनके स्वास्थ्य में सुधार भी दिखा था। लेकिन नियति के आगे यत बिंगड़ी और दुनिया भर को ठाहके लगावाने वाला यह कलाकार हमेशा गानपुर की मिट्टी की खुशबू को दुनिया भर में अपने किरदार के जरिये राजू छल और तनाव में क्यों न हों, राजू श्रीवास्तव की कामेडी उनके चेहरे पर के इस जादूगर का कार्यक्रम जिस शहर में हो जाता था, उदासी उस शहर भी बड़ा प्रोग्राम क्यों न हो राजू श्रीवास्तव के बगैर अधूरा अधूरा सा लगता। मन मसोस कर विधाता के विधान पर रोने के अलावा और किया ही क्या एर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। कामेडी के जरिये उन्होंने पर देश फूट फूट कर रो भी रहा है। उन्होंने अपनी कला के जरिये यह गों के दिलों तक पहुंचा जा सकता है। लोगों को हंसाते हंसाते उनके चरित्र नकीं निजता कुछ और ही थी वे निजी जिंदगी में बेहद ही गंभीर थे। उन्होंने धैर्य, शैक्षिक, सामाजिक और नैतिक समस्याओं को समेटा था। हंसते, गुदगुदाते देते थे। अपनी विधा के माध्यम से वे सरकारों को सवालों में खड़ा कर देते हंसते हंसाते आईना दिखा देते थे। उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया। पहले वे समाजवादी पार्टी में रहे फिर भाजपा में शामिल हो गये थे। उन्हें नए साप्ताहिकियों पर भी।

खक जेम्स प्रीमैन बिजनेस', व्यापारिक लेन-देन के आकांक्षाओं के प्रति तिथि



का अभूतपूर्व सग्रह हुआ है। जिसका एक बड़ा हिस्सा जन कल्याण में खर्च हो रहा है। स्टार्टअप इंडिया और वैचर कैपिटल फंडिंग की नयी संस्कृति के चलते नवोदयमों की राह आसान हुई है। देश में यूनिकॉर्न की संख्या का सौ से अधिक हो जाना इसका बड़ा प्रमाण है। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड अभियान के चलते गत वर्ष भारत ने 418 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया, जो देश की विनिर्माण व बढ़ती सेवा क्षमता का प्रमाण है। इन्हीं सबका का फल है कि भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अभिपर्व सम्मान हासिल किया है।

गाद करते हुए भगवान बिरसा
की जयंती 15 नवंबर को
गतीय गौरव दिवस घोषित किया
तो स्कूल-कॉलेज में जनजातीय
की भागीदारी बढ़ाने हेतु संबद्ध
में विशेष छात्रावास, शुल्क माफी
वित्तीय सहायता की पेशकश,
गतीय समाज की भाषा-संस्कृति
संरक्षित करने के साथ-साथ
य शिक्षा नीति-2020' में खेल
में विशेष जोर दिया गया है।
गतीय बच्चों के लिए एकलव्य
नवयों की संख्या में पांच गुना वर्द्धि
है। उच्च शिक्षा के स्तर पर
गतीय-औपधीय प्रथाओं, वन प्रबंध
रंपरिक (जैविक) फसल की खेती,
तेक खेती आदि में विशिष्ट
क्रम को बढ़ावा दिया जायेगा।
मंत्रालय और यूजीसी इन दिशाओं
में से कार्य कर रहे हैं। मोदी
पर द्वारा लाये गये परिवर्तन न
तात्कालिक, बल्कि दीर्घकालिक
तों पर भी खेरे उत्तरने वाले हैं।
त है तो बस जनता को अपना
स बनाये रखने की और प्रधानमंत्री
द्वारा दिखायी गयी राह पर
मी से चलते रहने की। एक नये
आत्मनिर्भर भारत, जगदगुरु
और स्वर्णिम भारत का स्वप्न

